इकाई 12 लॉकः संविधानवाद और सीमित सरकार *

संरचना

12.0 उद्देश्य
12.1 प्रस्तावना
12.2 सामाजिक अनुबंध का निर्माण
12.3 संवैधानिक सीमित सरकार
12.3.1 सहमति की भूमिका
12.3.2 असहमति का अधिकार
12.4 लॉक के संविधानवाद की विरासत
12.5 सारांश
12.6 कुछ उपयोगी संदर्भ
12.7 अपनी प्रगति जांचे अभ्यासों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक, जॉन लॉक के संवैधानिकता और सीमित सरकार के विचारों की प्रकृति और प्रमुख पहलुओं से परिचित कराना है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इस योग्य हो जाएंगेः

- लॉक के सामाजिक अनुबंध की प्रकृति का वर्णन करने में
- सीमित सरकार पर लॉक के विचारों की व्याख्या करने मे
- असहमति के अधिकार पर लॉक के दृष्टिकोण का परीक्षण करने में तथा
- लॉक के संविधानवाद और सीमित सरकार की विरासत का मूल्यांकन करने में।

12.1 प्रस्तावना

जॉन लॉक ने अपने प्रसिद्ध काम, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट (1689) में एक उदार, सीमित संवैधानिक सरकार की बात की जो जवाबदेह भी है। ऐसी सरकार की लॉक की अवधारणा प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों पर उनके विचारों की निरंतरता है, जिनकी पिछली इकाई में विस्तार से चर्चा की गई थी। लॉक का यह विश्वास कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार समाज से पहले के हैं और प्रकृति की स्थिति में मौजूद

*डॉ अभिरूचि ओझा, सहायक प्रोफेसर, राजनीति और शासन प्रभाग, कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय.

हैं, उन्हें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि किसी भी सरकार का गठन उनके अनुरूप काम करना है, न कि उनके उल्लंघन में। इसलिए, ऐसी सरकार को सबसे पहले केवल शासितों की सहमति से ही स्थापित करना पड़ता है, जिसके लिए एक सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता होती है।

लॉक ने अपने कुछ समकालीनों द्वारा प्रस्तुत इस विचार को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक निरंकुश सम्राट का समर्थन किया था कि एक सम्राट की शक्ति पितृ शक्ति के बराबर होती है यानी एक बच्चे पर पिता की शक्ति। लॉक का तर्क है कि पितृ शक्ति केवल बच्चों पर लागू होती है और वह भी तब तक जब तक वे तर्क की उम्र तक नहीं पहुंच जाते, जिसके बाद वे अपने लिए सोच सकते हैं और अब पितृ शक्ति के अधीन नहीं हैं। इसलिए, राजाओं की राजनीतिक शक्ति को पितृ शक्ति से तुलना करके उचित ठहराना बेतुका है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से झूठी धारणा पर निर्भर करेगा क्योंकि विषय बच्चे हैं जो तर्क नहीं कर सकते हैं। लॉक का यह भी तर्क है कि दाम्पत्य शक्ति भी सरकार की शक्तियों से तुलनीय नहीं है क्योंकि यह परिवार के क्षेत्र तक ही सीमित है और प्रकृति में राजनीतिक नहीं है। अपनी अवधि के दौरान राजनीतिक सत्ता के लिए इस तरह के लोकप्रिय औचित्य को खारिज करने के बाद, लॉक ने वैध राजनीतिक अधिकार पर अपने विचारों को विस्तार से बताया।

12.2 सामाजिक अनुबंध का निर्माण

लॉक के विचार में, एकमात्र वैध राजनीतिक प्राधिकरण वह है जो एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से स्थापित होता है जिसे लोगों द्वारा सहमति दी जाती है। हालांकि, इस तरह के एक सामाजिक अनुबंध से पहले और इसमें क्या शामिल हो सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है, लॉक को एक महत्वपूर्ण प्रश्न को संबोधित करना था कि लोग प्रकृति की स्थिति को क्यों छोड़ना चाहेंगे? हॉब्सियन प्रकृति की स्थिति एक हिंसक गड़बड़ी थी और इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि लोग इससे बचने के लिए क्यों उत्सुक होंगे। दूसरी ओर, जैसा कि पिछली इकाई में उल्लेख किया गया है, लॉक स्वयं तर्क देते हैं कि प्रकृति की अवस्था की उनकी अवधारणा में प्राकृतिक कानून के अनुसार शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व संभव है। अगर ऐसा है तो फिर सामाजिक अनुबंध और सरकार की आवश्यकता क्यों है?

लॉक इस प्रश्न का उत्तर इस ओर इशारा करते हुए देते हैं कि प्रकृति की स्थिति में नागरिक समाज द्वारा दिए गए तीन महत्वपूर्ण लाभों का अभाव है, "एक स्थापित, ज्ञात कानून", "एक ज्ञात और उदासीन न्यायाधीश" और "कानून का समर्थन करने की शक्ति"।

"सबसे पहले, एक स्थापित ज्ञात कानून होना चाहिए, जिसे आम सहमति से सही और गलत के मानक के रूप में अनुमति दी गई हो ... हालांकि प्रकृति का कानून सभी तर्कसंगत प्राणियों के लिए स्पष्ट और समझदार है; फिर भी पुरुष अपनी रुचि के पक्षपाती होने के साथ–साथ इसके अध्ययन के अभाव में अज्ञानी होने के कारण, इसे अपने लिए बाध्यकारी कानून के रूप में अनुमति देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं ... दूसरे, प्रकृति की स्थिति में एक ज्ञात और उदासीन न्यायाधीश होना चाहिए, स्थापित कानून के अनुसार सभी मतभेदों को निर्धारित करने के अधिकार के साथः उस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कानून के न्यायाधीश और उल्लघंनकर्त्ता दोनों होने के कारण, पुरुष स्वयं के लिए पक्षपाती

होने के कारण, जुनून और बदला उन्हें बहुत दूर ले जा सकता है ... तीसरा, प्रकृति की स्थिति अक्सर सजा का समर्थन करने और उसे उचित निष्पादन करने के लिए शक्ति होनी चाहिए" (लॉक, सरकार का दूसरा ग्रंथ, अध्याय IX)।

प्रकृति की स्थिति में प्राकृतिक कानून होते हैं, लेकिन चूंकि यह किसी राज्य के लिखित कानूनों के रूप में स्थापित, व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, इसलिए इसकी गलत व्याख्या हो सकती है। इसी तरह, जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति की स्थिति में प्राकृतिक कानून का निष्पादक है, एक स्वतंत्र न्यायाधीश की उपस्थिति फायदेमंद है क्योंकि यह कानूनों के निष्पादन में निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाता है। अंत में और शायद अधिक महत्वपूर्ण बात, एक आम प्राधिकरण की उपस्थिति कानून को लागू करने के लिए एक कार्यकारी के रूप में अधिकार का मतलब होगा कि कानूनों का उल्लंघन करने वालों को निश्चित रूप से राज्य की शक्ति से दंडित किया जाएगा। जबकि, प्रकृति की स्थिति में, यदि उल्लंघनकर्ता शक्तिशाली है, तो वह अपराधों से बच सकता है। इसलिए, नागरिक समाज के इन तीन लाभों को प्राप्त करने के लिए, लॉक का तर्क है कि लोग प्रकृति की स्थिति को छोड़ने और एक नागरिक समाज बनाने के लिए सहमत होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि लॉक द्वारा उल्लिखित ये तीन लाभ मोटे तौर पर एक विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों से मेल खाते हैं। लोगों के लिए प्रकृति की स्थिति को त्यागने की प्रेरणा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अपने प्राकृतिक अधिकारों को बेहतर ढंग से संरक्षित करना है। ऐसे लाभों की कमी के कारण प्रकृति की स्थिति अधिक आसानी से युद्ध की स्थिति में आ सकती है। यह विशेष रूप से धन की शुरूआत और सामाजिक असमानताओं के उदय के बाद अधिक संभावित है। इस प्रकार, संपत्ति वाले लोग नागरिक समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली बेहतर सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए यह सामाजिक अनुबंध के निर्माण की ओर जाता है।

एक नागरिक समाज में प्रवेश करके, लॉक का तर्क है कि लोगों को उन कुछ स्वतंत्रताओं और अधिकारों का त्याग करना पड़ता है जो उन्होंने प्रकृति की स्थिति में प्राप्त किए गए लाभों के बदले में प्राप्त की थीं। प्रकृति की स्थिति में, लोगों को जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे करने का अधिकार है, प्राकृतिक कानून की सीमा के भीतर। हालाँकि, एक बार नागरिक समाज में प्रवेश करने के बाद, इस स्वतंत्रता को आंशिक रूप से छोड़ना होगा क्योंकि नागरिक कानून का पालन सभी को करना होगा और यह प्राकृतिक कानून की तुलना में कठोर और अधिक विस्तृत होने की संभावना है। जैसा कि पिछली इकाई में उल्लेख किया गया है, प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी केवल प्राकृतिक कानून का पालन, सामाजिक स्वतंत्रता में परिवर्तित हो जाएगा, यानी नागरिक कानूनों का पालन जो किसी की सहमति से आता है।

"मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता पृथ्वी पर किसी भी श्रेष्ठ शक्ति से मुक्त होना है, और मनुष्य की इच्छा या विधायी अधिकार के अधीन नहीं है, बल्कि उसके शासन के लिए केवल प्रकृति का नियम है। समाज में मनुष्य की स्वतंत्रता किसी अन्य विधायी शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि वह है जो सहमति से, राष्ट्रमंडल में स्थापित है; न ही किसी वसीयत के प्रभुत्व के तहत, या किसी कानून के संयम के तहत, लेकिन वह विधायी क्या अधिनियमित करेगा, उसमें रखे गए लोगों के विश्वास के अनुसार "(लॉक, सेकेंड ट्रीटाइज आन गर्वनमेंट, अध्याय IV)।

प्रकृति की स्थिति में सभी के पास एक और शक्ति थी जिसे नागरिक समाज में प्रवेश करने के बाद पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है, वह है प्राकृतिक कानून के उल्लंघन को दंडित करने की प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति। एक नागरिक समाज में, अपराधों को सजा देने और दंडित करने की शक्ति न्यायाधीश और कार्यपालिका के पास होती है। इसलिए, एक बार सामाजिक अनुबंध के लिए सहमति देने और नागरिक समाज में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति कानून के न्यायाधीश और निष्पादक नहीं हो सकते।

अपनी प्रगति जाँचें अभ्यास 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) लॉक के अनुसार, प्रकृति की स्थिति पर नागरिक समाज द्वारा दिए जाने वाले तीन लाभ क्या हैं?

.....
.....
.....
.....
.....

2) एक बार नागरिक समाज में प्रवेश करने के बाद प्रकृति की स्थिति के किन विशेषाधिकारों को आंशिक और पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ता है?

.....
.....
.....
.....
.....

12.3 संवैधानिक सीमित सरकार

उन कारणों की व्याख्या करने के बाद जो प्रकृति की स्थिति में लोगों को एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक राष्ट्रमंडल के निर्माण के लिए सहमति देने के लिए प्रेरित करते हैं, लॉक यह दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रमंडल को सीमित, कुशल और नियंत्रण में रखने के लिए कैसे संरचित किया जाना चाहिए।

लॉक का तर्क है कि, एक बार सहमति के माध्यम से बनाए जाने के बाद, राष्ट्रमंडल के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत के सिद्धांत के आधार पर तय किए जाएंगे और जो लोग सामाजिक अनुबंध और राष्ट्रमंडल के निर्माण के लिए सहमत हैं, उन्हें बहुमत के सिद्धांत के अधीन रहने के लिए सहमति देनी होगी। जबकि सर्वसम्मत सहमति वांछनीय है, लॉक्स मानते हैं कि यह सभी परिदृश्यों में व्यावहारिक नहीं हो सकता है। राष्ट्रमंडल की वैधता

प्रजा के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा में विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और कार्यकारी शक्ति के समुचित कार्य पर निर्भर करेगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोंटेस्क्यू के बाद के वर्गीकरण के विपरीत, जिसमें न्यायिक शक्ति का अलग से उल्लेख किया गया है, लॉक के निर्माण में, न्यायिक शक्ति को कार्यकारी शक्ति के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

कॉमनवेल्थ के निर्माण के बाद बहुमत को सरकार के गठन पर निर्णय लेना होता है। लॉक के लिए, जो निकाय विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, वही सरकार के रूप को निर्धारित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के भीतर विधायी शक्ति सर्वोच्च है। बहुसंख्यक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे विधायी शक्तियों को अपने पास रखते हैं। वे विधायी शक्तियाँ देकर कुछ लोगों के हाथ में देकर एक कुलीनतंत्र स्थापित कर सकते हैं या एक व्यक्ति को शक्तियाँ देकर राजशाही स्थापित कर सकते हैं। सरकार का कोई भी रूप तब तक उपयुक्त है जब तक कि विधायी निकाय अपने जनादेश का अनुपालन करता है और अपनी सीमाएँ नहीं तोड़ता। हालांकि, लॉक किसी भी प्रकार के निर्वाचित, प्रतिनिधि विधायी निकाय के लिए वरीयता व्यक्त करता है और वह सरकार के मिश्रित रूपों में प्रयोगों का भी समर्थन करता है। एक बार निर्धारित होने के बाद, यह इस विधायी निकाय का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक कानून के अनुरूप और राष्ट्रमंडल के लाभ के लिए कानून बनाए। कॉमनवेल्थ का निर्माण और सरकार के रूप की स्थापना दो अलग–अलग कार्य हैं जिनमें पहला एक अनुबंध है और दूसरा एक मात्र अधिनियम है। इसका मतलब यह है कि बहुमत अगर विधायी निकाय को अक्षम या अक्षम पाते हैं या अपनी सीमा से आगे बढ़ते हुए पाते हैं तो वे किसी अन्य अधिनियम द्वारा सरकार के रूप को बदल सकते हैं। इस प्रकार, लॉक के लिए, अंतिम शक्ति उन लोगों के पास है जो राष्ट्रमंडल का गठन करते हैं, जबकि सरकार के भीतर विधायिका सर्वोच्च है। यही कारण है कि विधायिका अपनी शक्ति किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित नहीं कर सकती क्योंकि लोगों ने यह शक्ति केवल उन्हें दी है। लॉक कानूनों की प्रकृति पर कुछ शर्तों का भी सुझाव देते हैं जिन्हें विधायिका द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। सबसे पहले, उनका तर्क है कि विधायिका द्वारा रखे गए कानूनों को बिना किसी पक्षपात के सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्हें जनहित की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विधायिका को शामिल लोगों की उचित सहमति के बिना संपत्ति पर करों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। आखिरकार संपत्ति लॉक के लिए एक प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने विधायिका को अपनी सीमा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई व्यावहारिक सुझावों को भी सूचीबद्ध किया है। उदाहरण के लिए, वह विधायिका में लंबे समय तक सेवा करने वाले कुछ लोगों के बारे में चिंतित है, जिसके परिणामस्वरूप एक स्थायी राजनीतिक वर्ग बन जाता है जो खुद को बाकी समाज से अलग मानने लगता है। इसी तरह, वह यह नहीं समझते कि विधायिका के लिए हर समय सत्र में रहना या बार–बार मिलना भी आवश्यक है क्योंकि यह एक बार फिर उन्हें अपनी सीमा से परे कदम रखने के लिए प्रेरित कर सकता है।

लोगों ने एक संघीय शक्ति भी स्थापित की जिसकी भूमिका राष्ट्रमंडल के बाहरी संबंधों को चलाने की है। अन्य राज्यों के साथ संबंधों के संबंध में, लॉक का मानना है कि राष्ट्रमंडल को एक व्यक्ति के समान एक इकाई माना जाना चाहिए। यह व्यक्ति अन्य राज्यों के साथ प्रकृति की स्थिति में है क्योंकि कोई आम अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है। इसलिए, प्रकृति की स्थिति की उनकी अवधारणा के अनुसार, जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात आती है तो

प्राकृतिक कानून राज्यों के बीच लागू होता है। अन्य राज्यों के साथ राष्ट्रमंडल के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करने के लिए संघीय शक्ति की भूमिका है। संघीय शक्ति कार्यकारी शक्ति के अनुरूप काम कर सकती है।

लोगों को एक कार्यकारी शक्ति भी स्थापित करनी होती है जिस पर कानून के कार्यान्वयन का जिम्मा होता है। कार्यपालिका एक राजशाही या किसी अन्य उपयुक्त रूप का आकार ले सकती है। कार्यकारी पर कानून के कार्यान्वयन के साथ–साथ न्यायनिर्णयन दोनों का जिम्मा होता है क्योंकि न्यायिक शक्ति को भी लॉक द्वारा कार्यपालिका के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए, विधायी निकाय के बगल में, कार्यपालिका जो कि राष्ट्रमंडल में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। विधायी निकाय के विपरीत, जिसे अक्सर सत्र में होने की आवश्यकता नहीं होती है, लॉक कहते हैं कि विधायी निकाय द्वारा अधिनियमित कानूनों को ठीक से लागू करने के लिए कार्यपालिका को हर समय कार्य करने की आवश्यकता होती है। कार्यपालिका विधायी निकाय के अधीन है और विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकती है। हालांकि, लंबे समय तक अंग्रेजी राजनीति के करीबी पर्यवेक्षक रहे लॉक मानते हैं कि कभी–कभी अभूतपूर्व और अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें विधायिका द्वारा पहले से संबोधित करने में असमर्थ हो सकती है। इसमें अन्य राज्यों द्वारा आक्रामकता भी शामिल हो सकती है। इसलिए, लॉक कार्यपालिका को उन आकस्मिकताओं से निपटने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है जो स्पष्ट रूप से विधायिका द्वारा नहीं निपटाई जाती हैं। जहां कानून की खामोशी है, वहां कार्यपालिका के पास स्वयं कार्य करने के लिए जगह है। बहुत कम मौकों पर, कार्यपालिका ऐसे कानून के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जो बदले हुए परिदृश्य के कारण आम लोकहित के लिए हानिकारक हो गया है। चूंकि विधायी निकाय हमेशा सत्र में नहीं होता है, इसलिए इसे आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लग सकता है और इसलिए, कार्यपालिका को इन शक्तियों की आवश्यकता होती है ताकि तेजी से बढ़ती स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके।

"विवेक के अनुसार, सार्वजनिक भलाई के लिए, कानून के पर्चे के बिना, और कभी–कभी इसके खिलाफ भी कार्य करने की यह शक्ति वह है जिसे विशेषाधिकार कहा जाता है: क्योंकि कुछ सरकारों में कानून बनाने की शक्ति हमेशा अस्तित्व में नहीं होती है, और इतनी धीमी गति से; और क्योंकि यह पूर्वाभास करना भी असंभव है, और इसलिए कानूनों द्वारा सभी दुर्घटनाओं और आवश्यकताओं के लिए कानून निर्माण करना जो जनता से संबंधित हो सकते हैं, या ऐसे कानून बनाना जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर उन्हें सभी अवसरों पर कठोरता के साथ निष्पादित किया जाता है। , और उनके रास्ते में आने वाले सभी व्यक्तियों पर; इसलिए कार्यकारी शक्ति के लिए एक अक्षांश बचा है, पसंद के वह कई काम करने के लिए जो कानून निर्धारित नहीं करते हैं" (लॉक, सेकेंड ट्रीटाईज ऑफ गर्वन्मेन्ट, अध्याय, XIV)

लॉक द्वारा कार्यपालिका का विधायी सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। लॉक का तर्क है कि कार्यपालिका के विशेषाधिकार इस विश्वास पर आधारित हैं कि संस्था सामान्य भलाई के लिए सामाजिक अनुबंध की भावना के अनुसार कार्य करेगी। जब तक कार्यपालिका उस भरोसे का पालन करती है, तब तक उसके कार्य वैध रहते हैं लेकिन कोई भी उल्लंघन लोगों को कार्यपालिका को बदलने के लिए प्रेरित कर

सकता है। लॉक इस बात पर जोर देते हैं कि कार्यकारी विशेषाधिकार एक अधिकार नहीं बल्कि एक ट्रस्ट है। लॉक इस बिंदु पर जोर देता है क्योंकि कार्यपालिका का एक प्रबुद्ध नेता इस विश्वास का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकता है, जिससे कार्यकारी विशेषाधिकारों का विस्तार हो सकता है। इस विस्तारित कार्यकारी विशेषाधिकार को उत्तराधिकारी द्वारा मिसाल का हवाला देते हुए एक अविभाज्य अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है, जो लॉक यह तर्क देकर रोकना चाहता है कि यह एक अधिकार नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा रखा गया विश्वास है, जो इसे छीन सकते है।

पिछली चर्चा इंगित करती है कि लॉक सरकार के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कैसे प्राप्त करना चाहता है। जो लोग सामाजिक अनुबंध के लेखक हैं वे विधायी निकाय और कार्यपालिका के रूप को निर्धारित करते हैं और अंतिम अधिकार बनाए रखते हैं। लोगों द्वारा स्थापित संवैधानिक सीमाओं का कोई भी उल्लंघन विधायी निकाय और कार्यपालिका को अमान्य कर देगा। व्यापक अर्थों में, किसी को यह भी ध्यान रखना होगा कि लॉक ने राष्ट्रमंडल से प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने और व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करने की अपेक्षा की थी। इसलिए, सरकार और राष्ट्रमंडल के सभी संस्थानों को प्राकृतिक कानून का पालन करना होगा और सभी व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना होगा।

12.3.1 सहमति की भूमिका

वैध सरकार के लिए लॉकियन संवैधानिक ढांचे में सहमति की भूमिका पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत सहमति पर आधारित है कि लोग प्रकृति की स्थिति से बाहर निकलते हैं और एक राजनीतिक समाज यानी कॉमनवेल्थ का निर्माण करते हैं। इसी तरह, लॉक का यह भी तर्क है कि प्राकृतिक कानून द्वारा सभी पर लगाए गए सार्वभौमिक दायित्वों के अलावा, अन्य सभी दायित्वों को सहमति पर आधारित होना चाहिए। लॉक का दावा है कि एक व्यक्ति केवल व्यक्त सहमति देकर ही राजनीतिक समाज का पूर्ण सदस्य बन सकता है। हालाँकि, यह इस तथ्य के कारण समस्याग्रस्त हो जाता है कि वास्तविक समाजों में कुछ नागरिकों ने वास्तव में अपनी–अपनी सरकारों के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है। इस समस्या से अवगत लॉक ने मौन सहमति के अपने सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। लॉक का तर्क है कि एक कॉमनवेल्थ में रहना, सड़कों आदि जैसी सुविधाओं से लाभ उठाना, इसकी गतिविधियों में भाग लेना और एक विशेष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संपत्ति को विरासत में प्राप्त करके, लोग कॉमनवेल्थ को मौन सहमति देते हैं। जबकि अधिकांश लोगों ने राष्ट्रमंडल के लिए स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी हो, वे अंत में मौन सहमति देते हैं जो उनके विचार में भी मान्य है।

"मैं कहता हूं, कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास किसी भी सरकार के प्रभुत्व के किसी भी हिस्से की कोई संपत्ति, या आनंद है, वह अपनी मौन सहमति देता है, और इस तरह उस सरकार के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। आनंद, इसके तहत कोई भी; क्या यह उसका अधिकार उसके और उसके उत्तराधिकारियों के लिए हमेशा के लिए भूमि का हो, या केवल एक सप्ताह के लिए आवास; या फिर चाहे वह बमुश्किल राजमार्ग पर स्वतंत्र

रूप से यात्रा करना हो; और वास्तव में, यह उस सरकार के क्षेत्रों के भीतर इनमें से कोई गतिविधि हो'' (लॉक, सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गर्वन्मेंट, अध्याय VIII)

इसलिए, लॉक के लिए, सहमति प्रत्यक्ष, व्यक्त सहमति या अप्रत्यक्ष, मौन सहमति का रूप ले सकती है।

12.3.2 असहमति का अधिकार

हॉब्स के लिए वैध राजनीतिक शक्ति लोगों द्वारा उनके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से दी गई सहमति पर आधारित है। यह सामाजिक अनुबंध द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जाता है और लोकहित के लिए मौजूद है। इसके विपरीत, अत्याचारी शक्ति एक निरंकुश शक्ति है जिसका प्रयोग प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक अधिकारों की परवाह किए बिना अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति पर किया जाता है। यह एक राष्ट्रमंडल में विभिन्न तरीकों से हो सकता है। कार्यकारी या विधायी निकाय अपनी सीमा से अधिक हो सकता है या अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, जब लोग एक अत्याचारी शक्ति का सामना करते हैं जो अपनी वैध सीमाओं से परे अधिकार का प्रयोग करती हैं, लॉक जोर देकर कहते हैं कि लोगों को उस राष्ट्रमंडल का विरोध करने, विद्रोह करने और भंग करने का अधिकार है।

"जो कोई भी अधिकार के बिना बल का प्रयोग करता है, जैसा कि समाज में हर कोई करता है, जो बिना कानून के करता है, वह उन लोगों के साथ युद्ध की स्थिति में आता है जिनके खिलाफ वह इसका इस्तेमाल करता है; और उस स्थिति में सभी पूर्व संबंध रद्द कर दिए जाते हैं, अन्य सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, और प्रत्येक को अपनी रक्षा करने और हमलावर का विरोध करने का अधिकार है" (लॉक, सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गर्वन्मेंट, अध्याय XIX)

यह अधिकार इस तथ्य से आता है कि उनके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। इसलिए, यदि उनके प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो लोगों के पास राष्ट्रमंडल के कानूनों का पालन करना जारी रखने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उनके प्राकृतिक अधिकारों की प्रकृति की स्थिति में ही बेहतर ढंग से रक्षा की जाएगी। लॉक का तर्क है कि यदि कार्यपालिका या विधायिका ने सामाजिक अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है तो लोग अंततः न्याय करेंगे। लॉक का तर्क है कि लोगों को वैध सरकार की सीमाओं का उल्लंघन करने वालों को मारने या निष्पादित करने का भी अधिकार है।

अपनी प्रगति जाँचें अभ्यास 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) लॉक के अनुसार, कार्यकारी विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) लॉक के अनुसार, असहमति का औचित्य कब है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.4 लॉक के संविधानवाद की विरासत

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सीमित शक्तियों वाली संवैधानिक सरकार पर लॉक के विचारों ने दुनिया के कई महान संविधानों को प्रभावित किया है। इसने बाद के दार्शनिकों को भी प्रेरित किया और उदार राजनीतिक दर्शन में एक प्रमुख स्थान रखता है। लॉक के कुछ विचारों की भी काफी आलोचना हुई है। उदाहरण के लिए, लॉक की मौन सहमति के विचार पर कई विद्वानों ने सहमति के सिद्धांत को कमजोर करने का आरोप लगाया है, जो कि उनके दर्शन का मूल तत्व है। सीमन्स (1992) का तर्क है कि मौन सहमति का लॉकियन सिद्धांत लोगों को इसके बारे में जानकारी के बिना भी सहमति देने की अनुमति देता है, जो उनके विचार में अस्वीकार्य है। उनके विचार में, मौन सहमति एक निम्न स्तर का मानक है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि वैध राजनीतिक अधिकार के लिए महत्वपूर्ण होने पर लॉक के बार–बार जोर देने से उनके मौन सहमति के सिद्धांत से बहुत समझौता किया जाता है। हालांकि, डन (1969) का तर्क है कि लॉक सहमति शब्द का उपयोग अनिच्छा की कमी के लिए करते हैं, न कि जानबूझकर सकारात्मक सहमति के लिए। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति कॉमनवेल्थ में रहना जारी रखने को तैयार नहीं है, तो उसने सहमति दे दी है। दूसरी ओर, पिटकिन (1965) ने यह तर्क देते हुए लॉक की अधिक मौलिक व्याख्या की कि सहमति लॉकियन ढांचे के लिए केंद्रीय नहीं है। उनका तर्क है कि लॉक के सहमति के सिद्धांत को कमजोर करने का कारण यह है कि अंततः, एक राष्ट्रमंडल को सहमति के आधार पर नहीं, बल्कि प्राकृतिक कानून के पालन के आधार पर आंका जाता है। इस प्रकार, उनके विचार में, लॉक व्यक्त सहमति के महत्व को कम करता है क्योंकि उनके लिए प्राकृतिक कानून सहमति से अधिक महत्वपूर्ण था। वास्तविक सहमति क्या होती है और वैध राजनीतिक दायित्व के लिए इसके महत्व पर बहुत बहस जारी है।

इसके अलावा, अन्य प्राकृतिक अधिकारों पर संपत्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देने के लिए मैकफर्सन (1962) जैसे समाजवादी झुकाव वाले विद्वानों द्वारा लॉक की आलोचना की गई है, जिससे सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए केवल संपत्ति वाले लोगों को ही राष्ट्रमंडल की पूर्ण सदस्यता की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, विधायी निकाय में प्रतिनिधित्व पर चर्चा करते हुए, लॉक ने सुझाव दिया कि यह लोगों के कर योगदान पर आधारित हो सकता है, जिसका अर्थ यह होगा कि अधिक संपत्ति वाले लोग जो उच्च कर का भुगतान करते हैं, उनका विधायी निकाय में उच्च प्रतिनिधित्व होगा। यह मैकफर्सन की आलोचना का समर्थन करता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लॉक संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार मानते हैं और इसलिए, यहां तक कि विधायी निकाय भी प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लॉक कभी भी संबंधित लोगों की सहमति के बिना संपत्ति के पुनर्वितरण का समर्थन नहीं करेगा, भले ही विधायी निकाय चाहे। इसके अलावा, लॉक भी संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता दोनों के अधिकार को शामिल मानते हैं और इसलिए, कोई यह तर्क दे सकता है कि वह सभी प्राकृतिक अधिकारों के समान संरक्षण का समर्थन करता है। जबकि लॉक एक संपत्ति वाले व्यक्ति की संपत्ति को मनमाने ढंग से छीनने का समर्थन नहीं करेगा, वह समान रूप से संपत्ति के बिना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से छीनने का समर्थन नहीं करेगा। यह अभी भी सच हो सकता है कि लॉकियन कॉमनवेल्थ संपत्ति वर्ग के हितों की अधिक सेवा करेगा क्योंकि उनके पास संरक्षण के लिए अधिक संपत्ति है बजाय उनके जिनके पास संपति नहीं है।

लॉक के संप्रभुता के सिद्धांत की भी अस्पष्ट और असंगत होने के कारण आलोचना की गई है। विधायी निकाय को सरकार के भीतर सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लॉक उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनका कानून बनाते समय विधायी निकाय द्वारा पालन किया जाना है। एक सच्चा संप्रभु शर्तों के अधीन नहीं हो सकता। यही सिद्धांत कार्यपालिका को संप्रभु होने से अयोग्य ठहराता है। कॉमनवेल्थ बनाने वाले लोग भी प्राकृतिक कानून के अधीन ऐसा करते हैं। संप्रभुता की लॉकियन अवधारणा हॉब्स से मौलिक रूप से भिन्न है। हॉब्स के लिए, संप्रभु निर्विवाद, अविभाज्य, निरपेक्ष, शाश्वत शक्ति है जो अन्य शक्तियाँ होने के अलावा, कानून बनाती और उनका न्याय करती है। लॉकियन ढांचे में कोई तुलनीय संस्था या निकाय नहीं है। लॉकियन राजनीतिक दर्शन में एकमात्र निर्विवाद, निरपेक्ष और शाश्वत इकाई प्राकृतिक कानून है जो उसके लिए किसी भी अधिकार का वैध स्रोत है। सबाइन (1973) बताते हैं कि लॉक के पास अधिकार के कई स्तर हैं। यह व्यक्ति और उसके प्राकृतिक अधिकारों से शुरू होता है। कॉमनवेल्थ बनाने के लिए व्यक्ति एक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं और इसलिए, समुदाय प्राधिकरण के अगले स्तर का निर्माण करता है। हालाँकि, समुदाय व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। समुदाय के लोग, सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, विधायी निकाय बनाते हैं जो कानून बनाता है, लेकिन समुदाय के अधीन होता है। इसके अलावा, एक कार्यपालिका भी होती है जिसके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन विधायी के साथ–साथ समुदाय के नीचे होता है। हालाँकि, होब्सियन दृष्टिकोण से संप्रभुता के लॉकियन सिद्धांत की आलोचना करना उचित नहीं हो सकता है। संप्रभुता का लॉकियन ढांचा एक्विनास जैसे विद्वानों के अनुरूप है, जिन्होंने संप्रभुता को ईश्वर की तरह उच्च शक्ति या प्राकृतिक कानून और तर्क में विद्यमान माना। लॉक के लिए, प्राकृतिक कानून या इसके पीछे की शक्ति परम संप्रभु है, कोई मानव

संस्था नहीं। वह जो निर्माण करना चाहता है वह सरकार का एक रूप है जो इस उच्च सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना कार्य करेगा। इसलिए, लॉक का प्रयास एक सीमित सरकार बनाने का है जो व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। उस उद्देश्य के लिए, एक निरंकुश संप्रभु होने के बजाय, नियंत्रण और संतुलन के साथ प्राधिकरण के कई स्तरों का होना व्यावहारिक समझ में आता है।

12.5 सारांश

लॉक का तर्क है कि प्रकृति की स्थिति में कानून को लागू करने की शक्ति के साथ एक स्थापित कानून, एक निष्पक्ष न्यायाधीश और एक कार्यकारी की कमी के कारण, लोग एक सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए इच्छुक होंगे जो एक नागरिक समाज का निर्माण करता है ये लाभ होते हैं। सामाजिक अनुबंध से सहमत होकर, लोग आंशिक रूप से केवल प्राकृतिक कानून के अनुसार जीने की स्वतंत्रता छोड़ देते हैं। नागरिक समाज के निर्माण के लिए सहमति देकर, लोग नागरिक कानून का पालन करने के लिए सहमत होते हैं, जो प्राकृतिक कानून से अधिक कठोर हो सकता है। लोग प्राकृतिक कानून के उल्लंघन के लिए दूसरों का न्याय करने का अधिकार भी पूरी तरह से छोड़ देते हैं जो उनके पास प्रकृति की स्थिति में था। नागरिक समाज में, कानून के उल्लंघन का न्याय करना न्यायपालिका की भूमिका होगी। एक नागरिक समाज का निर्माण करने के बाद, लोगों ने प्राकृतिक कानून के अनुसार कानून बनाने के लिए एक विधायी निकाय की स्थापना की। उन्होंने विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी की स्थापना भी की। कार्यपालिका विधायी निकाय के अधीन है क्योंकि विधायी निकाय सरकार के भीतर सर्वोच्च शक्ति है। हालांकि, दोनों ही उन लोगों के अधीन हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है, जिन्हें उन्हें बदलने का अधिकार है यदि वे अपनी सीमाओं से बाहर जाएं। इस प्रकार, लॉक का यह भी तर्क है कि लोगों को एक ऐसी सरकार का विरोध करने और उसे उखाड़ फेंकने का अधिकार है जो अपनी सीमाओं के भीतर काम नहीं करती है और लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अधिकांश समकालीन संविधानों ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है और यही लॉक ने सत्ता के कई स्तरों का प्रस्ताव देकर आगे बढ़ाया है। इस प्रकार, कोई यह तर्क दे सकता है कि लॉक के दृष्टिकोण की इतिहास द्वारा पुष्टि की गई है।

12.6 कुछ उपयोगी संदर्भ

- एंस्टी. पी. (2011). *जॉन लॉक एंड नेचुरल फिलोसफी.* ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- एशक्राफ्ट. आर. (1986). *रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक्स टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट.* प्रिंसटन. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.
- चैपल. वी. (1994). *द कैम्ब्रिज कम्पेनियन टू लॉक.* कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
- कोलमैन. जे. (1983). *जॉन लॉक्स मोरल फिलोसफी.* एडिनबर्ग. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस.

- ग्रांट. आर. (1987). *जॉन लॉक्स लिबरलिज्म.* शिकागो. शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस.
- मैकफर्सन. सी. (1962). *द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्मः हॉब्स टू लॉक.* ओंटारियो. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- मेंडस. एस. (1991). *लॉक आन टोलरेशन इन फोकस.* लंदन. रूटलेज.
- सबाइन. जी. (1973). *ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी.* सैन डिएगो. ड्राइडन प्रेस.
- सीमन्स. ए.जे. (1992). *द लॉकियन थ्योरी ऑफ राइट्स.* प्रिंसटन. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.
- श्रीनिवासन. जी. (1995). *द लिमिट्स ऑफ लॉकियन राइट्स इन प्रॉपर्टी.* ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- स्ट्रॉस, लियो. (1953). *नेचुरल राइट एंड हिस्ट्री.* शिकागो. शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस.

12.7 अपनी प्रगति जांचे अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति जाँचें अभ्यास 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिएः

- प्रकृति की स्थिति में कोई स्थापित, ज्ञात कानून नहीं है
- प्रकृति की स्थिति में निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं है
- प्रकृति की स्थिति के पास कानून लागू करने और अपराधियों को दंडित करने की कार्यकारी शक्ति नहीं है

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिएः

- प्रकृति की स्थिति में प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को केवल प्राकृतिक कानून का पालन करना होता है। नागरिक समाज में प्रवेश करते समय इसे आंशिक रूप से छोड़ दिया जाता है क्योंकि अब नागरिक कानून का भी पालन करने की आवश्यकता है जो प्राकृतिक कानून से अधिक कठोर हो सकता है
- जब कोई नागरिक समाज में प्रवेश करता है तो प्राकृतिक कानून के उल्लंघन के लिए न्याय करने और दूसरों को दंडित करने का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है

अपनी प्रगति जाँचें अभ्यास 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिएः

- मौजूदा कानूनों द्वारा अभूतपूर्व और अप्रत्याशित आपात स्थितियों के दौरान सरकार को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए कार्यकारी विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है
- वे भरोसे पर आधारित हैं और अधिकार नहीं हैं

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिएः

- प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों से असहमति का अधिकार जो लॉकियन ढांचे में सर्वोच्च हैं
- चूंकि लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, यदि कोई निरंकुश शक्ति उत्पन्न होती है और उन अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो लोगों को विरोध करने का अधिकार है

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY